DEVELOPMENT) (SHRI G. VENNAT SWAMY): (a) Yes, Sir.

(b) As the available resources under JRY stand already committed, the request for additional funds for Maharashtra State can be considered only when additional funds or savings become available.

Construction of wells for SC/ST farmers in M. P.

2412. SHRI SURESH PACHOURI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have allocated funds to Madhya Pradesh for constructing wells free of cost on the fields of Scheduled Castes and Scheduled Tribes farmers of the State under a special central scheme;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) the number of such wells dug up so far in the State and what is the actual target of such wells in the State;

(d) the number of wells dug up so far in the Tribal areas of Madhya Pradesh and which are in working condition; and

(e) by when the rest of the wells are likely to be completed in the State?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) Yes, Sir.

(b) An amount of Rs. 4120.15 lakhs has been released as Central share against the State's share of Rs. 1030.04 lakhs.

(c) Agains the target of 33941 wells during the year 1992-93, 25845 wells have been dug up upto the end of June, 1992.

(d) 16770 wells.

(e) Rest of the wells are likely to be completed by end of March, 1993.

कुओं का निर्माण

2493. **श्री शिव प्रसाद जनपुरिया :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दस लाख कुओं के निर्माण की योजना के अंतर्गत 31 दिसम्बर, 1991 तक देश में कुल कितने कुओं का निर्माण किया गया तथा उनमें से कितने कुएं सफलतापूर्वक खोदे गये और कितने कुओं की खुदाई में सफलता प्राप्त नहीं हुई ;

(ख) सफलतापूर्वक खोदे गये कितने कुओं से कृषि भूमि की सिचाई की जा रही है तथा सींची जा रही कृषि भूमि का क्षेत्रफल कितना है; और

(ग) क्या सरकार पर्यावरण में सुधार तथा वृक्षारोपण से संबंधित कार्य में तेजी लाने के उद्देश्य से इस योजना के अंतर्गत निर्मित कुओं के आसपास दस वृक्षों के रोपण को अनिवार्य बनाने का विचार रखती है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) राज्य-सरकारों और संघशासित प्रशासनों से प्राप्त सूचना के अनुसार दस लाख कुओं के निर्माण की योजना के अंतर्गत अप्रैल, 1988 से दिसम्बर, 1991 की अवधि के दौरान 322195 कुओं का निर्माण किया गया था । खुदे कुओं जिनमें सफलता प्राप्त नहीं हुई, उनकी संख्या के बारे में सूचना की निगरानी नहीं की जाती है ।

(ख) दस लाख कुओं की योजना के अंतर्गत सिचाई के लिए खुले कुओं का निर्माण किया जाता है । सिचाई के लिए इस्तेमाल किए जा रहे कुओं की वास्तविक संख्या और उनके द्वारा सिंचित भूमि की निगरानी नहीं की जाती है क्योंकि वर्षा सहित कई अन्य कारणों से यह संख्या प्रति वर्ष भिन्न-भिन्न होगी । सामान्यत: एक खुले कुएं द्वारा सिंचाई प्रयोजन हेतु लगभग 2 हैक्टेयर भूमि क्षेत्र कवर किया जाता है ।

(ग) समाजिक वानिकी और फार्म वानिकि के अंतर्गत वृक्षारोपण जवाहर रोजगार योजना के कार्यों की एक स्वीकार्य मद है। तथापि, सरकार का दस लाख कुओं के निर्माण की योजना के अंतर्गत निर्मित कुओं के आस-पास 10 वृक्षों के रोपण को अनिवार्य बनाने का कोई विचार नहीं है।

बिहार में आदिवासी खेतिहर मजदूर

*2414. **डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :**
श्री रणजीत सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 जून, 1992 के "दि डेली टेलीग्राफ" में "एक्यूट पावर्टी इन ट्राइबल बिहार" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग द्वारा तैयार की गई सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह कहा गया है कि बिहार के आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी खेतिहर मजदूरों का बड़े पैमाने पर शोषण किया जा रहा है ;

(ग) यदि हां, तो क्या इन आदिवासी कर्मकारों का शोषण समाप्त करने के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में कोई विशेष योजना शामिल की गयी है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग द्वारा गठित अध्ययन दल ने बिहार में ग्रामीण असंतोष के बारे में किए गए त्वरित अध्ययन की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि "यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण असंतोष की जड़ मुट्ठी भर शोषणकारी भूस्वामियों द्वारा बहुसंख्यक मेहनती भूमिहीनों का शोषण और दमन करना है"

(ग) और (घ) आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिये योजना आयोग द्वारा गठित कार्यदल ने आदिवासी विकास के समूचे प्रश्न की समीक्षा की थी। कार्यदल ने सिफारिश की थी कि एक समन्वित नीति पर आधारित संतुलित सामाजिक-आर्थिक विकास पर मुख्य बल दिया जाना चाहिए और सामान्य सामुदायिक विकास कार्यक्रमों से भिन्न इस तरह के विकास कार्यक्रम बनाए जाने चाहिएं कि इनसे आदिवासियों और आदिवासी क्षेत्रों में व्याप्त प्रमुख समस्याओं का दिनान हो सके। अन्य बातों के साथ-साथ कार्यदल ने यह भी सिफारिश की थी कि आदिवासी समुदायों को हर तरह के शोषण से बचाया जाना चाहिए जिसके लिए कार्यदल ने कई उपायों की सिफारिश की है जिनमें भूमि के हस्तांतरण को रोकना तथा पहले से अंतरित भूमि की वापस बहाली और बंधुआ मजदूरों की मुक्ति के लिये कानून बनाना शामिल है।

गुजरात में ग्रामीण विकास परियोजनायें

2915. **श्री राम सिंह राठवा** : क्या **प्रधान मंत्री** रह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में ग्रामीण विकास परियोजनाओं का जिलावार ब्यौरा क्या है ;

(ख) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में इनमें से प्रत्येक परियोजना के लिए वर्षवार कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है ;

(ग) गुजरात के किन-किन जिलों में ये परियोजनाएं अपनी निर्धारित समय-सीमा से पीछे चल रही हैं ; और

(घ) इन सभी परियोजनाओं को उनके निर्धारित समय में पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) केन्द्र में ग्रामीण विकास परियोजनाओं के जिलावार ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।